



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]
No. 255]नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2000/कार्तिक 19, 1922
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2000/KARTIKA 19, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2000

विषय: इंडोनेशिया, ताइवान, थाइलैंड और मलेशिया से आंशिक विन्यासित यार्न (पी ओ वाई) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करना

फा. सं. 19/1/2000-डी जी ए डी.— एसोसिएशन ऑफ सिथैटिक फाइबर इंडस्ट्री ने आंशिक विन्यासित यार्न (पी ओ वाई) के लिए घरेलू उद्योग की ओर से 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें इंडोनेशिया, ताइवान, कोरिया गणराज्य, थाइलैंड और मलेशिया से आंशिक विन्यासित यार्न के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जाँच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पाद:** वर्तमान जाँच में शामिल उत्पाद इंडोनेशिया, ताइवान, कोरिया गणराज्य, थाइलैंड और मलेशिया के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित पोलिस्टर का आंशिक विन्यासित यार्न (जिसे इसके पश्चात सम्बद्ध वस्तु भी कहा गया है) है। आंशिक विन्यासित यार्न सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 5402.4200 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. **घरेलू उद्योग की स्थिति:** यह याचिका एसोसिएशन ऑफ सिथ्रेटिक फाइबर इंडस्ट्री, 125, उदय पार्क, प्रथम तल, नई दिल्ली-110049 द्वारा पी ओ वाई के लिए घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई है। देश में पी ओ वाई के 39 उत्पादक हैं जिनमें से पाँच उत्पादक कंपनियों ने जो नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने की पात्र हैं, याचिका का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। याचिका का समर्थन करने वाले दो अन्य उत्पादक नामतः मै0 इंडोरमा तथा मै0 डी सी एल पोलिएस्टर्स को नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने का पात्र नहीं पाया गया है क्योंकि ये पाटित वस्तु के निर्यातिक से संबंधित हैं (इंडोरमा) और स्वयं ही आरोपित पाटित वस्तु के आयातक हैं। संबद्ध वस्तु के पाँच पात्र उत्पादकों नामतः मै0 सेंचुरी एंका, मै0 जे सी टी लिमिटेड, मै0 रेमण्डस सिथ्रेटिक, मै0 संघी पोलिस्टर्स लिलो तथा मै0 रिलायन्स इंडस्ट्रीज का कुल उत्पादन जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 54 % बनता है। इसलिए याचिकाकर्ता उक्त पाँच पात्र उत्पादकों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त करके प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की अपेक्षित स्थिति में है।

3. **शामिल देश:** वर्तमान जांच में शामिल देश, जिनके विस्तृद्ध पाटन का आरोप लगाया गया है, वे हैं - इंडोनेशिया, ताइवान, कोरिया गणराज्य, थाइलैंड और मलेशिया (जिन्हें इसके बाद सम्बद्ध देश भी कहा गया है)।

4. **समान वस्तुएं** याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि भागीदार कंपनियों और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सम्बद्ध देशों से निर्यातित आंशिक विन्यासित यार्न (पी ओ वाई) में आमतौर पर कोई खास अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पी ओ वाई तथा इन देशों से आयातित पी ओ वाई भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, इसके कार्य और उपयोग तथा टैरिफ वर्गीकरण में समान हैं। इन दोनों का तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होने का दावा किया गया है और दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, घरेलू रूप से उत्पादित तथा सम्बद्ध देशों से आयातित पी ओ वाई को प्रथम दृष्टया पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तु माना जाता है।

5. पाटन एवं पाटन मार्जिन

(क) **सामान्य मूल्य:** याचिकाकर्ता ने परिकलित लागत के आधार पर विभिन्न देशों के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसकी जांच याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए छोरों और आंकड़ों के आधार पर की गई है। संदर्भाधीन संबद्ध देशों में पी ओ वाई के सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

(ख) **निर्यात कीमत:** संबद्ध देशों से हुए निर्यात की कीमत के संबंध में यथोचित सूचना उपलब्ध है, जो कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर आधारित है। समुद्री भाड़, समुद्री बीमे, कमीशन, स्वदेशी भाड़ और पत्तन व्यय के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

(ग) **पाटन मार्जिन:** उपर दिए गए साक्ष्यों के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि कोरिया गणराज्य के मामले को छोड़कर, जहाँ निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से अधिक है, संबद्ध देशों के मामले में पाटन हुआ है। अन्य संबद्ध देशों नामतः ताइवान, इंडोनेशिया, थाइलैंड और मलेशिया के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

इससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि इंडोनेशिया, ताइवान, थाइलैंड और मलेशिया के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है । इसलिए इन देशों को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश के रूप में माना जाता है ।

6. क्षति और कारणात्मक संबंध: लाभप्रदता, बिक्री प्राप्ति जैसे घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतकों तथा आयातों की मात्रा एवं कीमत जैसे संकेतकों से प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । इस बात का भी कोई प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

7. पाटनरोधी जांच की शुरुआत: पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा और उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करसे हैं ।

8. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर 1999 तक की है ।

9. सूचना प्रस्तुत करना: संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित ढंग से संबंधित सूचना तथा अपने विचार प्राधिकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पाटनरोधी प्रभाग, उद्योग भवन नई दिल्ली - 11011 को भेज दें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अपने अनुरोध कर सकती है ।

10. समय सीमा: वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए । तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में हितबद्ध पार्टियों को उनके प्रत्युत्तर हेतु समय बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे ।

11. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण : नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के बाद उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

12. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या निर्धारित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2000

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Partially Oriented Yarn (POY) from Indonesia, Taiwan, Thailand and Malaysia.

F. No. 19/1/2000-DGAD.— Association of Synthetic Fibre Industry, on behalf of the domestic industry for Partially Oriented Yarn(POY), has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Partially Oriented Yarn from Indonesia, Taiwan, Korea RP, Thailand and Malaysia and requested for anti-dumping investigation and levy of anti-dumping duties.

1. **Product Involved :** The product involved in the present investigation is Partially Oriented Yarn of Polyester (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from Indonesia, Taiwan, Korea RP, Thailand and Malaysia. Partially Oriented Yarn is classified under customs sub-heading No. 5402.4200 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however only indicative and in no way binding on the present investigation.

2. **Domestic Industry Standing:** The petition is filed by the Association of Synthetic Fibre Industry, 125, Uday Park, 1st Floor, New Delhi-110049 on behalf of the domestic industry for POY. There are 39 producers of POY in the country out of which five producer companies, eligible to form part of the domestic industry under the Rules, have expressly supported the petition. Two other producers supporting the petition namely, M/s Indorama and M/s DCL Polyesters, are found ineligible to form part of domestic industry under the Rules as they are related to the exporter of the dumped articles (Indorama) and importers of the allegedly dumped articles themselves. The total production of the subject goods of the five eligible producers, namely, M/s Century Enka, M/s JCT Limited, M/s Raymonds Synthetics, M/s Sanghi Polyesters Ltd. and M/s Reliance Industries, during the POI, constitutes 54% of the total production of the domestic industry. Therefore, the petitioner having the express support of the said five eligible producers, prima-facie, has the requisite standing to file the petition on behalf of the domestic industry.

3. **Countries involved :** The countries involved in the present petition against which dumping has been alleged are Indonesia, Taiwan, Korea RP, Thailand and Malaysia (also referred to as subject countries hereinafter).

4. **Like Articles :** It is claimed by the petitioner that there is no significant difference in the goods produced by the participating companies and the Indian industry in general and the Partially Oriented Yarn(POY) exported from the subject countries. POY produced by the Indian industry and that imported from these countries are similar in physical and chemical characteristics, manufacturing process, functions and uses and in tariff classification. The two are claimed to be technically and commercially substitutable and both are used interchangeably. Therefore, the POY domestically produced and that imported from the subject countries are prima-facie treated as like articles within the meaning of the anti dumping Rules.

5. **Dumping and Dumping margin :**

- (a) **Normal value :** The petitioner have claimed normal value for different countries on the basis of the constructed cost which has been examined in the light of the data and figures furnished by the petitioner. There is sufficient prima-facie evidence with regard to normal value of POY in the subject countries under reference.
- (b) **Export price :** Reasonable information is available with regard to export price from the subject countries which is based on the DGCI&S data. Adjustments are claimed on Ocean freight, Marine insurance, Commission, Inland freight and Port expenditure. Thus, there is prima-facie evidence of export price at ex-factory level from the subject countries.
- (c) **Dumping Margin :** Comparison of the Normal Value and Export Price, calculated on the basis of evidence as detailed above, prima-facie indicates dumping in the case of the subject countries except in the case of Korea RP, where the export price is higher than the Normal Value. For other subject countries, namely, Taiwan, Indonesia, Thailand and Malaysia, the dumping margin is significantly higher than the de-minimis limit.

This prima-facie indicates that the subject goods are being dumped in India by the exporters of Indonesia, Taiwan, Thailand and Malaysia. These countries are, therefore, treated as subject countries for the purpose of the present investigation.

6. **Injury and Causal Link** : The various economic indicators relating to domestic industry such as profitability, sales realisation and indicators such as volume and price of imports indicate *prima-facie* that the domestic industry has suffered material injury. There is also *prima-facie* evidence that the dumped imports of the product under consideration from the subject countries have caused injury to the domestic industry.

7. **Initiation of Anti-Dumping Investigation** : The Designated Authority, in view of the foregoing, initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

8. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st January, 1999 to 31st December, 1999.

9. **Submission of Information**: The exporters in the subject countries and the known importers of the subject goods in India are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce and Industry, Deptt. of Commerce, Anti-Dumping Division, Udyog Bhawan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. **Time Limit** : Any information relating to present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are, however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately. The Designated Authority, in no circumstances, will grant to the interested parties extension of time for their response.

11. **Inspection of public file** : In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limit set out.

12. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within the stipulated period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

